पेट्रोकेमिकल जोन में 3 माह में भूखंड आवंटन, 6 माह में शुरू हों औद्योगिक इकाइयां : मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा ने बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित कर निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन का प्रमुख केंद्र बन रहा है। इसके सुनियोजित विकास से प्रदेश में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तीन माह में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए तथा आवंटन के छह माह

- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रिफाइनरी के उप-उत्पाद रियायती दरों पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए

के भीतर संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री शनिवार को राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूखंड आवंटन केवल औपचारिकता नहीं रहे, बल्कि वहां निर्धारित समय में वास्तविक औद्योगिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। शेष उपलब्ध भूखंडों का शीघ्र नीलामी के माध्यम से आवंटन करने तथा भूखंड



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली।

मिलने के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

रिफाइनरी के उत्पादों का प्रदेश में उपयोग हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी से प्राप्त होने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उपयोग प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में ही सुनिश्चित किया जाए। इससे स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा और उद्योगों की लागत एवं आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी।

उन्होंने सीमेंट, पाइप सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उपयोग की संभावनाओं का आकलन करने तथा वर्तमान मांग, उपभोग और भविष्य की जरूरतों का अध्ययन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी आवश्यकताओं और सुझावों के आधार पर समस्याओं का समाधान करने को कहा, ताकि मजबूत औद्योगिक तंत्र विकसित हो सके।

निवेशकों को मिलेगा रियायती दरों पर बाय-प्रोडक्ट

मुख्यमंत्री ने बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित कर अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफाइनरी अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को रिफाइनरी के उप-उत्पाद रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और प्लग एंड प्ले सहित अन्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, उद्योग विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव स्व. ए.वी. सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जल संसाधन मंत्री रावत ने

स्वर्गीय ए.वी.सिंह राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार के ससुर थे

जयपुर (कासं)। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त स्वर्गीय ए.वी. सिंह की स्मृति में शनिवार को भोपाल स्थित आईएएस मेस, चार इमली में तीये की बैठक हुई। इस अवसर पर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने स्वर्गीय सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

ज्ञात रहे कि स्वर्गीय ए.वी. सिंह, राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार के ससुर थे। स्व. ए.वी. सिंह का जन्म 22 अक्टूबर 1944 को हुआ था तथा 11 नवंबर 2026 को उनका निधन हुआ। वे मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

श्रद्धांजलि सभा में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व मुख्य सचिवों, मित्र- परिजनों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय सिंह के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए और उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता, सरल स्वभाव तथा जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों को याद किया।

इस अवसर पर धीरज माथुर, पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहार, रंजना चौधरी, अशोक 'छोटू' नोरोन्हा, प्रदीप बैजल, ए.के. अग्रवाल, स्नेहलता श्रीवास्तव ने कविता के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राजिंदर सिंह 'लालजी', रफू मियां, अरविंद खरे, पूर्व मुख्य सचिव बी.पी. सिंह, मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव, डॉ. वसुंधरा सिंह, टी.सी.ए. राघवन, स्वराज पुरी, अरुणेश्वर सिंहदेव तथा वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में अंजलि सिंह ने परिवार की ओर से भावपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय सिंह के जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए।

एसएमएस अस्पताल में दवा, जांच और ब्लड सैंपल की सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में अब ओपीडी मरीजों को दवाइयां लेने,जांचों का बिल बनवाने और ब्लड सैंपल देने के लिए अलग-अलग जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अस्पताल परिसर में इन सभी सुविधाओं के लिए एक समर्पित भवन बनाया जा रहा है। इसमें 13 विंडो और 30 बिल काउंटर होंगे। यह सुविधा मार्च 2027 से शुरू करने की तैयारी है।

- मार्च 2027 से शुरू होगी सुविधा, नई बिल्डिंग में बनेंगी 13 विंडो और 30 बिल काउंटर

नई बिल्डिंग धन्वंतरी ओपीडी ब्लॉक के पास बनाई जा रही है। इससे मरीज डॉक्टर को दिखाने के बाद सीधे इस भवन में पहुंच सकेंगे। यहां जांचों का बिल बनवाने, ब्लड सैंपल देने और दवाइयां लेने की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मरीज आसानी से घर जा सकेंगे।

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि वर्तमान में धन्वंतरी ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के बाद मरीजों को जांचों का बिल बनवाने और ब्लड सैंपल देने के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता है। इससे उन्हें काफी समय लगता है और जानकारी के लिए इधर-उधर पूछताछ करनी पड़ती है। नई व्यवस्था शुरू होने से मरीजों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेंगी और अस्पताल के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे। जोशी ने बताया कि नई बिल्डिंग में दवाइयों के वितरण के लिए दो अलग-अलग फ्लोर पर बड़े डीडीसी सेंटर बनाए जाएंगे। प्रत्येक डीडीसी सेंटर पर 15 विंडो होंगी, जहां से मरीजों को विभिन्न प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

वर्तमान में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स सहित अलग-अलग विभागों की दवाइयों के लिए अलग-अलग डीडीसी सेंटर संचालित हैं। नई व्यवस्था से दवा वितरण सहित जांच और ब्लड सैंपल की प्रक्रिया को एक ही परिसर में व्यवस्थित किया जा सकेगा।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में सीबीआई ने सात राज्यों के 33 ठिकानों पर छापे मारे

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिले सुरागों पर सीबीआई ने एक्शन लिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात राज्यों के 33 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सीबीआई की टीमें अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर और दुर्ग सहित कई शहरों में तलाशी अभियान चला रही हैं। इसके अलावा इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर में भी दबिश दी गई है। जांच एजेंसी की टीमें महादेव एप से जुड़े लोगों, उनके ठिकानों

- कई जगहों पर सट्टेबाजी के पैनल बंद कराए, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त

और संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में साक्ष्य जुटा रही हैं। ओमान से प्रत्यर्पित होकर भारत लाए गए मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारियों और सुरागों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इसे महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के खिलाफ सीबीआई की अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल संचालित मिले। सीबीआई ने इन्हें बंद कराया। मौके से डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में इन दस्तावेजों से म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए पैसों के लेन-देन से जुड़े सुराग मिलने की बात सामने आई है।गौरतलब है कि सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने 1 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया था।

रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पूछताछ के दौरान महादेव एप के संचालन और भारत में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की बात कही गई है। फिलहाल सीबीआई की छापेमारी जारी है। कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

सूने मकान से 3.50 लाख रु. और गहने चोरी

जयपुर। नारायण विहार थाना इलाके में दीपावली पर सूने मकान को निशाना बनाकर बदमाश लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के गहने और 3.50 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए। स्विफ्ट कार से आए तीन-चार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि मांग्यावास स्थित ज्योति विहार निवासी अरुण झालानी (34) ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिवादी दीपावली के त्योहार पर जयपुर से बाहर रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके सूने मकान को निशाना बनाया और घर में रखे सोने-चांदी के गहने, सिक्के और 3.50 लाख रुपए नकद चोरी कर ली।



गुलाबी नगरी जयपुर में दिवाली का त्योहार व सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए इन दिनों देशी-विदेशी पर्यटक आए हुए हैं। जहां एक तरफ जयपुर के तमाम पर्यटन स्थल ''पावणो'' से गुलजार हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को एम.आई.रोड पर सांगानेरी गेट से लेकर अजमेरी गेट और रामनिवास बाग की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, यहां लगी वाहनों की लंबी कतारों ने काफी देर तक यातायात व्यवस्था की परीक्षा ली। फोटो-राष्ट्रदूत

ड्राई फ्रूट्स के नाम पर बुजुर्ग से 3.29 लाख रुपए ठगे

जयपुर। जवाहर सर्किल इलाके में 63 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ऑनलाइन साइबर ठगी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर दिया था। इसके बाद ठगों ने जीएसटी के नाम पर सामान अटकने और भुगतान वापस करने का झांसा देकर उन्हें पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट पर प्रक्रिया करते ही बुजुर्ग के एचडीएफसी बैंक खाते से 9 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 3 लाख 29 हजार 987 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि पंचशील एन्क्लेव निवासी संजय मोजिस सैम्युल (63) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 5 नवंबर को उन्होंने श्रीराम ड्राई फ्रूट्स के व्हाट्सऐप नंबर पर संपर्क कर ड्राई फ्रूट्स का ऑर्डर दिया था। बताए गए तरीके से उन्होंने 4 हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसके दो दिन

- व्हाट्सऐप पर जीएसटी के नाम पर सामान अटकने का झांसा दिया

बाद व्हाट्सऐप कॉल के जरिए एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। उसने बताया कि जीएसटी के कारण उनका सामान अटक गया है और वह भुगतान वापस करना चाहते हैं। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने दो फर्जी स्क्रीनशॉट भी भेजे। इसके बाद बुजुर्ग के मोबाइल पर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी गई। बुजुर्ग ने जैसे ही रिक्वेस्ट पर प्रक्रिया की, उनके एचडीएफसी बैंक खाते से 9 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 3,29,987 रुपए कट गए। खाते से बड़ी रकम निकलने पर उन्हें अपने साथ हुई साइबर ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर व्हाट्सएप नंबर और बैंक खातों के लेनदेन के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

भ्रष्टाचार के मामले में जेडीए का प्रवर्तन अधिकारी बरी

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित कुमार पारीक को दोषमुक्त कर दिया है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश ललित कुमार पारीक की अपील पर दिए। अदालत ने जांच में गंभीर खामियों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता को आधार बनाते हुए एसीबी कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

अदालत ने पाया कि डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सील बंद अवस्था में नहीं रखा गया था। मालखाना प्रभारी और रिकॉर्डिंग तैयार करने वाले गवाहों ने स्वीकार किया कि डीवीआर खुली अवस्था में था और 25 जुलाई 2006 से पहले सीडी किस हालत में रही, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनिवार्य कानूनी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। एसीबी

- राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाए

अधिकारियों ने न तो परिवादी और न ही आरोपी के मोबाइल फोन या सिम कार्ड को जब्त किया और न ही कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त की। परिवादी की शिकायत की तारीख, रनिंग नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट और चॉक एफआईआर की तारीखों और समय में भारी अंतर व विसंगतियां थीं। एसीबी अधिकारियों की ओर से गवाहों के बयान महीनों और साल भर की देरी से दर्ज किए गए, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके अलावा परिवादी शंकरलाल और सह-परिवादी नंदकिशोर ट्रायल के दौरान पूरी तरह पक्षद्रोही हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि एसीबी के दबाव में और दलाल मनोज शर्मा के इशारे पर झूठी कार्रवाई की गई थी। स्वतंत्र गवाहों ने भी कभी रिश्वत की मांग या पैसों के लेन-देन को अपनी आंखों से देखने या सुनने से इंकार किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी ने सभी बयानों और पत्रावलियों का बारीकी से अवलोकन किए बिना मात्र मशीनी अंदाज में स्वीकृति जारी कर दी।

मामले से जुड़े अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने बताया कि परिवादी शंकर लाल ने 14 जुलाई, 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि वह अपनी कृषि भूमि मे निर्माण करा रहा है। इस दौरान तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित कुमार पारीक ने आकर काम रुकवा दिया और अगले दिन आकर रिश्वत मांगी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने ललित कुमार पारीक को गिरफ्तार किया था। वहीं एसीबी कोर्ट ने 18 नवंबर, 2019 को उसे दो साल की सजा और बीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था।

बाड़ेबंदी में प्रत्याशियों पर भी नजर रखेगी कांग्रेस, पाला बदलने की आशंका से अलर्ट

हर जिले से नियमित फीडबैक ले रहे नेता, प्रत्याशियों से मुलाकातों पर भी सख्ती बढ़ाई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में जीत के बाद पार्टी प्रत्याशियों के पाला बदलने की आशंका को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी दूसरे दलों के खेमे में नहीं चले जाएं, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अभी से व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां पार्टी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन से जुड़े नेताओं की विशेष टीम प्रदेशभर के प्रत्येक जिले की चुनावी गतिविधियों पर नजर रख रही है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तैनात यह टीम जिला स्तर पर नियुक्त किए गए पार्टी नेताओं से नियमित रूप से फीडबैक ले रही है। इसमें प्रत्याशियों

- बताया जा रहा है कि, जिन होटल और रिसॉर्ट में कांग्रेस प्रत्याशियों को ठहराया गया है, वहां बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। संबंधित होटल और रिसॉर्ट प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्याशियों से केवल अधिकृत व्यक्ति ही मुलाकात कर सकेंगे।

की गतिविधियों, बाड़ेबंदी की व्यवस्थाओं और विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव परिणाम आने के बाद किसी भी स्थिति में उसके जीते हुए प्रत्याशी पाला बदलकर दूसरे दलों में शामिल न हों। इसके लिए बाड़ेबंदी में रह रहे प्रत्याशियों की दैनिक गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

जिन होटल और रिसॉर्ट में कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है, वहां बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। संबंधित होटल और रिसॉर्ट प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्याशियों से केवल अधिकृत व्यक्ति ही मुलाकात कर सकेंगे। यहां तक कि प्रत्याशियों के नजदीकी परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों को भी मुलाकात से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। पार्टी किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, जिससे चुनाव परिणाम के बाद उसके प्रत्याशियों के खेमे में सेंध लग सके।प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश में सत्ता की चाबी भाजपा के पास है और भाजपा नगर निकाय चुनाव की तरह पंचायत राज चुनाव में भी अधिक से अधिक जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ऐसे में जिन जिलों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, वहां भाजपा दूसरे दलों के जीते हुए प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकती है। कांग्रेस नेतृत्व को आशंका है कि भाजपा की नजर उसके जीते हुए प्रत्याशियों पर भी हो सकती है। इसी संभावना को देखते हुए पार्टी ने बाड़ेबंदी और निगरानी की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है।

प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिलों में पंचायत राज चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को भी प्रत्याशियों के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थानों पर प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है, वहां पार्टी के मौजूदा विधायक, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ नेता नियमित रूप से उनसे संवाद कर रहे हैं। इन नेताओं के माध्यम से प्रत्याशियों को पार्टी की नीतियों, नियमों और सिद्धांतों की याद दिलाई जा रही है तथा हर हाल में पार्टी के साथ जुड़े रहने की सीख दी जा रही है। साथ ही उन्हें समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

कुल मिलाकर, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस केवल जीत की रणनीति ही नहीं बना रही, बल्कि चुनाव परिणाम के बाद अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए भी पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस की यह निगरानी व्यवस्था अब पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गई है।

'44 लाख परिवार अब भी नल कनेक्शन के इंतजार में'

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बजट में आंकड़ों की पाइपलाइन बिछा रही है, जबकि प्रदेश के 44 लाख परिवार आज भी नल कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मौजूदा रफ्तार से इन परिवारों तक पानी पहुंचाने में 30 साल से अधिक समय लग सकता है। गहलोत ने अपनी नई वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला वीडियो जारी करते हुए जल जीवन मिशन के कामकाज की कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल से तुलना की। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस अंतर पर जवाब मांगा। गहलोत के अनुसार, अब हर शनिवार को एक वीडियो जारी किया जाएगा, जिसमें सरकार की किसी बड़ी बजट घोषणा को उठाकर पूछा जाएगा कि घोषणा के मुकाबले धरातल पर कितना काम हुआ है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक साल में 13.88 लाख नल कनेक्शन दिए गए, जबकि भाजपा सरकार ने तीन साल में 12.95 लाख कनेक्शन दिए हैं।

कीमती सामान चोरी

जयपुर। मानसरोवर इलाके में सूने मकान को निशाना बनाकर तीन बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। बदमाश मकान की दीवार फांदकर अंदर घुसे और पानी की मोटर, पाइप, मशीन सहित कीमती सामान प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ले गए।

पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मानसरोवर थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार मानसरोवर निवासी सुमित भार्गव ने रिपोर्ट में बताया कि 10 नवंबर को परिवार बाहर था, पीछे से बदमाशों ने वारदात की।

गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया : जलदाय मंत्री

जयपुर (कासं)। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ''बजट फाइल्स'' नाम से जारी वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, आज उसी योजना पर गहलोत सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तो ''नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'' वाली कहावत को सिद्ध करने जैसा है।

- पिछली कांग्रेस सरकार ने कागजों में पाइपलाइनें बिछाई, बिना कनेक्शन टंकियां बनाई : मंत्री कन्हैयालाल चौधरी

चौधरी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से 2023 के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के कारण प्रदेश की छवि धूमिल हुई। कागजों में पाइपलाइन बिछाने, बिना कनेक्शन टंकियां बनाने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन जलदाय मंत्री को भी इस मामले में जेल जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था।

एक हजार करोड़ का बजट हुआ लैप्स

जलदाय मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार के समय योजना का एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट लैप्स हो गया और निर्धारित समय सीमा भी समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से योजना की समय सीमा बढ़वाई तथा लैप्स हुए बजट का सदुपयोग सुनिश्चित कर योजना को गति दी। वर्तमान सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी से पूरा कर रही है और अब तक 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने गहलोत से सवाल किया कि उनके कार्यकाल में पाइपलाइनें कागजों में क्यों बिछाई गईं, टंकियों को कनेक्शन क्यों नहीं दिए गए और योजना में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई।

जल आत्मनिर्भरता के लिए 26 हजार करोड़ के कार्यादेश

चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जल सुरक्षा और जल आत्मनिर्भरता के लिए बड़े कदम उठा रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 26 हजार करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौते और किशाऊ बांध समझौते के माध्यम से प्रदेश के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, जबकि वर्तमान सरकार योजना को पटरी पर लाकर राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। कांग्रेस शासनकाल की हकीकत जनता जानती है और वीडियो जारी कर पूर्ववर्ती सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकती।